E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2021; 3(2): 86-89
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 14-08-2021
Accepted: 19-09-2021

डॉ. कमल कान्त शर्मा
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर,
राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
डॉ. कमल कान्त शर्मा
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर,
राजस्थान, भारत

भारत में उच्च शिक्षा व वैश्विकरण की चुनौतियां: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. कमल कान्त शर्मा

सारांश
प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत भारत में उच्च शिक्षा तथा आधुनिक समय की मांग के अनुसार वैश्वीकरण की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया गया है जिसके अंतर्गत ऐसी चुनौतियों के विश्लेषण को इस अध्ययन में सम्मिलित किया गया है जिनकी की उपस्थिति में किसी भी राष्ट्र की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत के संदर्भ में भी यह स्थिति अत्यंत ही विचारणीय है अतः इस विषय पर अध्ययन करना नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा संबंधित विषय के पेशेवरो हेतु अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन इस बात की भी समीक्षा करता है कि किस प्रकार वैश्वीकरण ने अपने दोहरे स्वरूप से विश्व के लगभग सभी राष्ट्रो को प्रभावित करने का काम किया है।

मूल शब्द - भारतीय उच्च शिक्षा, वैश्विकरण, वैश्विक ग्राम (Global Village), वैदिक शिक्षा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

प्रस्तावना
उच्च शिक्षा, सामान्य शिक्षा के उद्देश्यो से ऊपर उठकर किसी विशेष विषय से संबंधित शिक्षा अथवा विषय का बोध कराती है। शिक्षा प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि शिक्षित लोगो से परिपूर्ण समाज ही कल्याणकारी समाज का द्योतक माना गया है। क्योंकि अशिक्षा मानसिक परतंत्रता का विकास करती है । भारतीय संस्कृति में शिक्षा तथा मानव अधिकारों की प्राचीन काल से ही वकालत होती आई है जिसके सर्वोत्तम उदाहरण तत्कालीन रचित वेद वेदांगों तथा उपनिषदों के स्वरूप में वर्तमान में भी देखने को मिलते हैं। भारतीय शिक्षा का स्वरूप व विकास निरंतर परिवर्तित होता रहा है जिसे हमने वैदिक काल की शिक्षा, उत्तर वैदिक शिक्षा, बौद्ध काल की शिक्षा, मुगल काल की शिक्षा, ब्रिटिश काल की शिक्षा तथा स्वतंत्रता पूर्व काल की शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के रूप में देखा है। शिक्षा के उक्त ऐतिहासिक कालक्रम के प्रत्येक चरण में तत्कालीन आचार्यो, गुरूओ, शिक्षकों अथवा शिक्षाविदों द्वारा सामयिक चुनोतियो का सामना किया गया है जिसके परिणामस्वरूप हम आज की शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को देख रहे हैं। वास्तव में शिक्षा व शैक्षिक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होना एक सजीव सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। परंतु इसकी कुछेक चुनोतिया वर्तमान समय में भी समाज के पिछड़े तथा त्रस्त वर्गो को इससे लाभांवित होने और अपना विकास कर सकने में अवरोध उत्पन्न करती हैं। हालाँकि विश्व ग्राम की कल्पना ने उच्च शिक्षा के अवसरों में बढ़ोतरी तो की है। वास्तव में वैश्विकरण की अवधारणा नई नहीं हैं परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था में वैश्विकरण की तीव्र वृद्धि ने असंभव संभावनाओ की तलाश की है।

अध्ययन के उद्देश्य
प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऐतिहासिक कालक्रम पर प्रकाश डालते हुए आधुनिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में ऐसी चुनोतियों का विश्लेषण करना

है जिसके केंद्र में राष्ट्र निर्माण हेतू अत्यंत आवश्यक समझी जाने वाली उच्च शिक्षा को रखा गया है। इसके अतिरिक्त वैश्विक ग्राम (Global village) की संभावनाओ के समक्ष उत्पन्न राष्ट्रीय चुनोतियों के संबंध में भी समझ को विकसित करना है ताकि भारत को भी विश्व के विकसित राष्ट्रो के समतुल्य ही वैश्विक पथ प्रदर्शक के रूप में चिन्हित किया जा सके।

अध्ययन प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु द्वितीयक आंकड़ो से प्राप्त ज्ञान को आधार मानते हुए विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत पूर्व में की गई शोधों, चर्चित पुस्तकों तथा समाचार पत्रों द्वारा प्राप्त विवेचनाओ को आधार बनाया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में शिक्षा का इतिहास उतना ही प्राचीन, ऐतिहासिक तथा गौरवमयी रहा है जितना की पृथ्वी पर मानव सभ्यता का विकास। भारतीय ऐतिहासिक कालक्रम में वैदिक शिक्षा के स्वरूप में प्रारंभिक परिवर्तनों के कारण ही नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक शिक्षा के सफल परिणामों को वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, तथा ऋचाओं की रचनाओ के रूप में देखने को मिलता है। परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते वैदिक कालीन शिक्षा में धार्मिक आडंबरो तथा ब्राह्मणवाद के वर्चस्व ने समाज के एक त्रस्त वर्ग में नवीन विचारधारा को जन्म दिया जिसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ तथा बौद्ध कालीन शिक्षा अस्तित्व में आई। बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था समाज के प्रत्येक वर्गों के साथ-साथ महिलाओं तथा शूद्रों के लिए भी उपयुक्त सिद्ध हुई। इसके पश्चात हम भारतीय इतिहास में मुगल कालीन शिक्षा के अस्तित्व को देखते हैं। तत्कालीन शिक्षण व्यवस्था में 'मकतब ' व्यवस्था होती है जिसमें लड़के और लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुगल काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, गुजरात, लाहौर, सियालकोट आदि मुख्य रूप से प्रसिद्ध रहें हैं। मुगल काल के हुमायुं तथा अकबर जैसे शासकों द्वारा 'शेर मंडल' जैसे पुस्तकालयों तथा 'आईने अकबरी' जैसी पुस्तकों की रचना की गई। मुगलिया सल्तनत के क्षीण होते ही भारत में ब्रिटिश कालीन सत्ता ने शिक्षा के स्वरूप को पूर्णरूपेण परिवर्तित करने का प्रयास किया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बनी जिसने भारतीय संस्कृति के मूल्यों को चुन चुन कर नष्ट करने का काम किया। परंतु भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना जो 1858 मे की गई थी, के द्वारा उच्च शिक्षा को व्यवस्थित करने के प्रयास किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में 1980 तक तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। जिसे समझने हेतु निम्न आंकड़ो को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। वर्ष 1980 तक जहा भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 132 तथा महाविद्यालयों की संख्या 4738 थी जबकि इसके पश्चात इस दिशा में बहुत तेजी से प्रयास किये गये जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 348 तथा महाविद्यालयों की संख्या भी 17625 हो गई। वर्तमान में भारतीय शिक्षा व्यवस्था अमेरिका तथा चीन के पश्चात विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। भारत में उच्च शिक्षा अथवा सभी वर्गों हेतु अनिवार्य शिक्षा की माँग सदैव से रही है। भारतीय उच्च शिक्षा में राजनीति के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता है। चूँकि भारतीय उच्च शिक्षा का राजनीतिकरण आंतरिक राजनीति के साथ गुंथा हुआ है। जिसने समय समय पर अपने वोट बैंक के उद्देश्यों की पूर्ति की अथवा सत्ता के विपक्ष में रहकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है।

भारत में उच्च शिक्षा की चुनातियाँ

1. संसाधनों का अभाव

प्राय यह देखा गया है कि भारत अभावों से ग्रस्त समाज है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा के अंतर्गत चयन प्रक्रिया राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों अथवा संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संपन्न की जाती हैं। परंतु तुलनात्मक रूप से राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों को कम अनुदान प्राप्त होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के निर्धारित बजट का तकरीबन 65 फ़ीसदी हिस्सा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के रूप में प्राप्त होता है जबकि शेष35 % ही राज्य विश्वविद्यालयों को मिल पाता है।

2. शिक्षकों की रिक्तिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंकड़ों के आधार पर भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों मे प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों तथा असिस्टेंट प्रोफेसरों के क्रमश 16,699, 4,731 और 9,585 पद स्वीकृत हैं परंतु वर्तमान मे प्रोफेसरों के के 35%, एसोसिएट प्रोफेसरों के 46% तथा असिस्टेंट प्रोफेसरों के लगभग 26 फीसदी पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों के रिक्त रह जाने के प्रमुख कारण हैं कि, " युवा विद्यार्थियों को शिक्षण का पेशा आकर्षण नहीं लगता " तथा इन पदों को भरने की चयन प्रक्रिया अत्यंत ही लंबी अथवा जटिल है। इसमें प्रक्रियागत औपचारिकताएं बहुत अधिक है जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

तालिका 1: विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रिक्तियाँ स्रोत: UGC

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	स्वीकृत पद	रिक्त पद
Central Universities	16,699	6,542
Indian Institute of Management	618	111
Indian Institute of Technology	5,092	1,611
Indian Institute of Information Technology	224	103
National Institute of Technology	4,291	1,497

भारत के अधिकतर राज्यों के विश्वविद्यालयों में भी यह समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है क्योंकि प्रत्येक वर्ष छात्रों के नामांकन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है । जिसने शिक्षकों के अभाव की समस्या को उजागर किया है।

3. दोष युक्त परीक्षा प्रणाली

वर्तमान शिक्षा प्रणाली का शिक्षा तथा मानव जीवन के मूल्यों से कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता है । वर्तमान शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य परीक्षा परिणामों के रूप में आत्महत्याओ, विद्यालय त्यक्त विधार्थियो की संख्या मे बढ़ोतरी, एकांगी तथा बेकार लक्ष्य विहीन युवाओं का सृजन करना हो गया है। परीक्षाओं का उद्देश्य केवल उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक लाना हो चुका है तथा परिक्षार्थीयों द्वारा रटतं शैली को अपनाना उनके मानसिक स्वरूप का सर्वाधिक कमजोर पक्ष बनता जा रहा है।

डॉ राधाकृष्णनजी जी कहते हैं कि, " आज की शिक्षा विधार्थियो को बौद्धिक दृष्टि से निर्धन, हृदय से कठोर तथा शारीरिक दृष्टि से बौना बनाती है। " अत परीक्षा समग्र व्यक्तित्व विकास पर बल नहीं देती है । शिक्षण के यह महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय केवल धन जुटाने का साधन बनती जा रही हैं। महाविद्यालयों में तो वर्ष में मात्र 30 दिन उपस्थित रहकर परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर लेना ही लक्ष्य बनता जा रहा है।

4. शिक्षा का व्यापारीकरण/ निजीकरण

भारत में शिक्षा का बाजारूपन मंडियों में शिक्षा के क्रय-विक्रय के रूप में उभरता जा रहा है। निजी स्तर के महाविद्यालयों तथा कोचिंग संस्थानों ने शिक्षा को अत्यंत ही महंगा तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अथवा शिक्षा के अधिकार पर धन तथा बल का प्रभाव दृष्टिगत हो चुका है। निजीकरण का सीधा प्रभाव गरीबों, शोषितों, किसानों तथा मजदूरी द्वारा जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों पर पड़ता है। जिसे निम्न आंकड़ों द्वारा समझा जा सकता है। भारत में 80 फीसदी बच्चे निजी स्वामित्व वाले स्कूलों मे अध्ययनरत हैं जबकि मात्र 20 फीसदी बच्चे ही नगर निगम अथवा सरकारी स्कूलों मे अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में फीस तथा अन्य खर्चे इतने महंगे हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए शिक्षा से वंचित रह जाना ही अंतिम परिणाम है।

वैश्विकरण की चुनोतियों का विश्लेषण

वैश्वीकरण की अवधारणा को "वसुधैवकुटुम्बकम्" के समतुल्य समझा गया है जिस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व की वकालत करता है उसी प्रकार वैश्वीकरण वैश्विक स्तर पर ज्ञान तथा विचारों को अभिव्यक्त करने तथा उनके आदान प्रदान करने का पक्षधर रहा है। यह अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है जिससे विश्व का कोई भी राष्ट्र अछूता नही रहा है। वैश्विकरण ने समस्त राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित करने का काम किया है। शिक्षा के संदर्भ में वैश्वीकरण का संबंध मानव शक्ति के निर्माण को बढ़ाकर विश्व प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार करने से है। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण द्वारा शिक्षा की सर्व उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। वैश्वीकरण विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समस्या के समाधान में भी अपनी भूमिका निभाता है। साथ ही वैश्वीकरण की यह अवधारणा राष्ट्रों को अपने आर्थिक विकास में भी योगदान देती है क्योंकि किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र को किसी न किसी वस्तु अथवा आवश्यकता हेतु किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर रहना ही पड़ता है।

थॉमस फाइडमैन के अनुसार, वैश्विकरण वास्तव में बाजारों, अर्थव्यवस्था और प्रोद्योगिकियों का एकीकरण है । इसमें विश्व का मध्यम से छोटे रूप में ऐसा संकुचन हो रहा है जिससे हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक इतनी जल्दी और सस्ते में पहुँच जाये जितने में पहले कभी संभव नहीं था । पूर्व की सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओ की भाँति यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में घरेलू राजनीतिज्ञों, आर्थिक नीतियों तथा देशों के विदेशी संबंधो को स्वरूप प्रदान कर रहा है। "

वैश्वीकरण की कुछ अपनी गंभीर चुनौतियां भी हैं जिनके परिणामस्वरूप यह अवधारणा निर्धनों, किसानों व आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों अथवा राष्ट्रों हेतु अत्यंत ही दयनीय स्थिति का निर्धारण करती है । जिसके अंतर्गत कुछ एक चुनौतियों का विश्लेषण यहां किया गया है ताकि वैश्वीकरण की अवधारणा को सार्वभौमिक बनाया जा सके अर्थात ऐसी वैश्वीकरण व्यवस्था का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके जो समाज के प्रत्येक वर्ग का समानांतर विकास करने में सक्षम सिद्ध हो।

1. वैश्वीकरण के उद्देश्यों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को ही स्थान दिया गया है यदि उत्पादन में गुणवत्ता का अभाव होगा तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संसाधनों की कमी वाले राष्ट्र अथवा पिछड़े राष्ट्रों को विकास की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता बल्कि यह चुनौती विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य की खाई को और भी बढ़ाने का काम करती है।
2. विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के पश्चात भारत के लिए यह स्थिति अत्यंत ही गंभीर हो जाती है । यदि समय रहते योजनाबद्ध तरीकों से नागरिकों को जन जागरूक किये बगैर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्रियान्वित किया गया तो लाभ के बदले हमें अधिक हानि हो सकती है।
3. वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों, उपकरणों तथा वस्तुओ पर विचार करने पर स्पष्ट होता है कि उत्पादकता, गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों आदि के आधार पर अन्य देशों की तुलना में भारत की क्या स्थिति है। एशिया महाद्वीप में जापान कोरिया तथा चाइना जैसे राष्ट्र हमारे सामने एक चुनौती की तरह उभर रहे हैं।
4. वैश्वीकरण आर्थिक सामाजिक कल्याण के लिए भी अत्यंत ही घातक सिद्ध हुआ है वैश्वीकरण से रोजगार के अवसरों में कमी तथा आय असमानता जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई है। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि अमीर और अमीर बनता जा रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है।
5. मूल्यपरक प्रतिस्पर्धा भी विकासशील राष्ट्रों के लिए एक जटिल स्थिति है । वैश्विक बाजार में जो भी देश सस्ती वस्तुओं का उत्पादन कर सकेगा वही विजय की स्थिति में पहुंचेगा। इस प्रकार विकासशील अथवा पिछड़े राष्ट्रों का अमेरिका,यूरोप और चाइना के समक्ष टिक पाना

लगभग नामुमकिन है। इस प्रकार विश्व संपन्न तथा विपन्न राष्ट्रो में विभाजित होता जा रहा है।

6. वैश्वीकरण के समक्ष आतंकवाद भी एक अत्यंत ही गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है। कई आतंकवादी गतिविधियों तथा युवाओं को बरगलाने में आतंकवादी संगठनों द्वारा वैश्वीकरण को मंच बनाया जा रहा है। आतंकवाद एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा कोई संगठित समूह अथवा दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हिंसा का योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करता है । दैनिक समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस के 28 July 2005 के अंक में प्रकाशित शरद अविनाश द्वारा लिखित लेख " आतंकवाद लाइलाज बनती त्रासदी" का एक अंश यहा सम्मिलित करना अति आवश्यक है ताकि वैश्विकरण की गंभीर चुनोती को सुगमता पूर्वक विश्लेषण किया जा सके।

"द्विध्रुवीय विश्व के राष्ट्रो के बीच आपसी वेमनस्य और उनकी एक दूसरे को उखाड़ फेंकने की गलत चेष्टाओ ने ही आज इन आतंकवादी संगठनों को संगठित करने और उन्हें सुदृढ रूप से स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया है। इन राष्ट्रों ने अपने अपने पक्ष मजबूत करने के उद्देश्य से इन संगठनों को न केवल हथियार बल्कि प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं दिलाकर अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की, बाद में उनकी इन्हीं नीतियों ने अमेरिका और रूस को आतंकवाद की धधकती आग में झोंक दिया।"

इसी प्रकार पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का उपयोग भारत जैसे पडोसी राष्ट्रो की राष्ट्रीय एकता व अखंडता को भंग करने में किया जाता रहा है जो कि अत्यंत ही चिंतनीय विषय है। जिसके उदाहरण हम भारत में 26/11 और अमेरिका में 9/11 जैसे आतंकी हमलों के रूप में पूर्व में देख भी चुके हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन का विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे "भारत में शैक्षिक विकास अथवा नियोजन के प्रयास निष्प्रभावी क्यों रहे? " के संबंध में सुधार की संभावनाओं को जन्म देता है। यह अध्ययन भारत के समकक्ष ही विकासशील देशों अथवा हमसे भी पिछड़े राष्ट्रो में तुलनात्मक रूप से उच्च शिक्षा के प्रभावी तथा पूर्ण विकसित हो जाने के मुख्य आधारों पर विवेचन करने की महत्ता पर भी ध्यान केंद्रित करती है। उच्च शिक्षा में उपस्थित चुनौतियों के अतिरिक्त वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के समतुल्य संभावनाओं को विकसित करने के उद्देश्यों पर भी कार्य किए जाने की अति आवश्यकता है। वैश्वीकरण के इस दौर में भारत को किस प्रकार विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित करवाया जाए तथा आतंकवाद जैसी चुनोतियो से निपटने हेतु एक सख़्त राष्ट्रीय नीति का निर्वहन कर उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। वैश्विकरण के मानको में परिवर्तन कर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित किये जाने की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत उन क्षेत्रों की विकास यात्रा को भी लाभ प्राप्त हो सके जिन्हे प्रतिस्पर्धा रूपी इस वैश्विक अवधारणा ने पिछडा तथा बौना बना दिया है।

संदर्भ सूची

1. पवन अग्रवाल, भारत में उच्च शिक्षा के पांच दशक: फ़िलिप जी अल्टबाख के निबंधों का संकलन, Sage Publications pvt. Ltd. New Delhi वर्ष 2018
2. PRS legislative Report .स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का सारांश Institute for policy research Studies New Delhi वर्ष 2017
3. दीनानाथ बत्रा, भारतीय शिक्षा का स्वरूप, वर्ष 2014
4. बी एस शेखावत, आम आदमी और लोकतंत्र, प्रभात प्रकाशन, वर्ष 2006
5. शरद अविनाश, आतंकवाद लाइलाज बनती त्रासदी, इंडियन एक्सप्रेस (दैनिक समाचार), 28 जुलाई 2005
6. अवनीश सिंह, नए भारत की नीव राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, प्रभात प्रकाशन, वर्ष 2021
7. डॉ मनीष खरे, डॉ. बबीता वर्मा, भारत में शिक्षा- नीति की दशा और दिशा, श्री विनायक प्रकाशन वर्ष 2021